



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 320]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 4, 2016/आश्विन 12, 1938

No. 320]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 4, 2016/ASVINA 12, 1938

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर, 2016

विषय : चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित आफ्लोक्सेसिन के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच

सं. 14/06/2016-डीजीएडी.—मै. आरती ड्रग्स लि. (जिसे आगे आवेदक कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष चीन (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित आफ्लोक्सेसिन (जिसे आगे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने और पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया है।

2. और यतः प्राधिकारी प्रथम दृष्टया यह पाते हैं कि पाटनरोधी जांच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा कथित पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं, इसलिए प्राधिकारी एतद्वारा नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की जांच की शुरूआत करते हैं ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

3. यह आवेदन मै. आरती ड्रग्स लि. द्वारा विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उद्योग के रूप में दायर किया गया है। आवेदक के अलावा भारत में संबद्ध वस्तु के कुछ अन्य उत्पादक हैं।
4. मै. आरती ड्रग्स लि. ने यह बताते हुए एक घोषणा-पत्र प्रस्तुत किया है कि उन्होंने संबद्ध देश से पीयूसी का आयात नहीं किया है। उन्होंने यह भी घोषित किया है कि वे संबद्ध देश में पीयूसी के किसी निर्यातक या उत्पादक से या भारत में पीयूसी के किसी आयातक से संबंधित नहीं हैं।
5. रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार आवेदक का उत्पादन समान वस्तु के सकल घरेलू उत्पादन में 'प्रमुख हिस्सा' बनता है। अतः प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि याचिकाकर्ता पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के अर्थ के भीतर पात्र घरेलू उद्योग हैं और आवेदन संबंधित नियमावली के नियम 5 (3) के अनुसार योग्यता संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

विचाराधीन उत्पाद

6. वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद 'ओफ्लोक्सेसिन' है।
7. ओफ्लोक्सेसिन फ्लोरोक्विनोलोन ड्रग श्रेणी का एक सिंथेटिक कीमोथेराप्युटिक एंटीबायोटिक है जिसे दूसरी पीढ़ी का फ्लोरोक्विनोलोन माना जाता है। ओफ्लोक्सिन एक रेसमिक मिश्रण होता है जिसमें 50 प्रतिशत लिवोफ्लोक्सिन (जैविक सक्रिय संघटक) और 50 प्रतिशत उसका 'मिरर इमेज' या इनेंसेमर डेक्स्ट्राफ्लोक्सिन होता है। ओफ्लोक्सेसिन का प्रयोग ब्रोंसिटिस, निमोनिया सहित त्वचा संक्रमणों और, ब्लेडर, यूरिनरी ट्रेक्ट, प्रजनन अंगों और प्रोस्टेट ग्लैंड के संक्रमणों का उपचार करने में किया जाता है। यह संक्रमण फैलाने वाले बैक्टेरिया को मारकर कार्य करता है।
8. विचाराधीन उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 30 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 30 के अंतर्गत पीयूसी का विशिष्ट एचएस कोड 3004 20 34 है। तथापि संबद्ध वस्तु के बल्क ड्रग होने के कारण इसका आयात एचएस कोडों अर्थात् 2915, 2916, 2918, 2941 के अधीन भी होता है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान उत्पाद के दायरे पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।

समान वस्तु

9. आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध वस्तु और आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। जैसा आवेदक ने बताया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित ओफ्लोक्सेसिन और संबद्ध देश से आयातित ओफ्लोक्सेसिन भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए नियमावली के अंतर्गत इन्हें 'समान वस्तु' माना जाना चाहिए। अतः प्राधिकारी वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु के 'समान वस्तु' मानते हैं।

शामिल देश

10. वर्तमान जाँच चीन जन. गण. (जिसे 'संबद्ध देश' भी कहा गया है) से विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन से संबंधित है।

सामान्य मूल्य

11. आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए और चीन के मामले में नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 और 8 के अनुसार सामान्य मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए। आवेदकों ने भारत में उत्पादन लागत को विधिवत रूप से समायोजित करके चीन जन. गण. में सामान्य मूल्य का दावा किया है। नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 8 के अनुसार यह माना जाता है कि चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तु के उत्पादक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों के अधीन कार्य कर रहे हैं।

12. उक्त गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की मान्यता और चीन जन. गण. में प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा उसके खंडन के अधीन चीन जन. गण. के लिए संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य का अनुमान नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 के अनुसार लगाया गया है।

निर्यात कीमत

13. आवेदक द्वारा निर्यात कीमत को आईबीआईएस के सौदा-वार आयात आकड़ों से प्राप्त आकड़ों के आधार पर निर्धारित किया गया है। निवल निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, पत्तन व्यय, अंतरदेशीय भाड़े, बैंक प्रभार और वैट के लिए समायोजन सहित कीमत संबंधी समायोजन किये गये हैं।

पाटन मार्जिन

14. सामान्य मूल्य की तुलना कारखाना द्वार स्तर पर निर्यात कीमत के साथ की गई है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना द्वार निर्यात कीमत से अधिक है, जिससे यह पता चलता है कि संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है। इस प्रकार अनुमानित पाटन मार्जिन निर्धारित न्यूनतम सीमा से काफी अधिक है।

क्षति और कारणात्मक संबंध

15. यतः प्राधिकारी प्रथम दृष्टया यह पाते हैं कि पाटनरोधी जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा कथित पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य हैं, प्राधिकारी एतद्वारा नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की जांच की शुरुआत करते हैं ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

जांच अवधि (पीओआई)

16. प्रस्तावित जाँच अवधि (पीओआई) 1 जुलाई, 2015 से 30 जून 2016 तक की है। तथापि क्षति जाँच अवधि पर अप्रैल 13 – मार्च 14, अप्रैल 14 – मार्च 15, अप्रैल 15 – मार्च 16 और जाँचकी प्रस्तावित अवधि शामिल करने का विचार और प्रस्ताव किया गया है।

सूचना प्रस्तुत करना

17. संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार, उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों व प्रयोक्ताओं को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने तथा प्राधिकारी को अपने विचारों से निम्नलिखित पते पर अवगत कराने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है:-

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग,
नई दिल्ली- 110001

18. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है।

समय-सीमा

19. वर्तमान जाँच से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई के लिए कोई अनुरोध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

20. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जांच की शुरूआत की तारीख से 40 दिनों के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपाय जारी रखने की जरूरत अथवा अन्यथा के बारे में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।

अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

21. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के संबंध में" गोपनीयता "का दावा किया जाता है तो ऐसे मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और (ख). अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) प्रस्तुत करना होगा। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए।

22. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय पाठ की पाँच (5) प्रतियां प्रस्तुत करना जरूरी होगा।

23. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/या ऐसी सूचना का सारांशकरण क्यों संभव नहीं है।

24. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध /रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

25. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

26. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

27. नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

असहयोग

28. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

ए. के. भल्ला, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th October, 2016

Subject: Anti Dumping investigation concerning imports of Ofloxacin originating in or exported from China.

No. 14/06/2016-DGAD.—M/s Aarti Drugs Ltd. (hereinafter referred to as the applicant) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) for initiation of anti-dumping investigation and imposition of anti-dumping duty concerning imports of Ofloxacin (hereinafter also referred to as the subject goods), originating in or exported from China (hereinafter also referred to as the subject country).

2. And whereas, the Authority prima facie finds that sufficient evidence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject country, 'injury' to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and 'injury' exist to justify initiation of an anti-dumping investigation; the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of Rule 5 of the Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of anti dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the 'injury' to the domestic industry.

Domestic Industry & Standing

3. The Application has been filed by M/s Aarti Drugs Ltd., as domestic industry of the product under consideration. Apart from the applicant, there are some other producers of subject goods in India. The total production of Ofloxacin in India has been estimated on the basis of consumption of O-Acid in the Country

4. M/s Aarti Drugs Ltd. has furnished a declaration stating that they have not imported the PUC from the subject country. They have further declared that they are not related either to any exporter or producer of the PUC in the subject country or any importer of the PUC in India.

5. As per the evidence available on record, the production of the applicant accounts for a major proportion in the gross domestic production of the like article. The Authority, therefore, determines that the applicant constitutes eligible domestic industry within the meaning of Rule 2 (b) of the Anti-Dumping Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Rules supra.

Product under consideration

6. The product under consideration for the purpose of present investigation is "Ofloxacin".

7. Ofloxacin is a synthetic chemotherapeutic antibiotic of the fluoroquinolone drug class considered to be a second-generation fluoroquinolone. Ofloxacin is a racemic mixture, which consists of 50% levofloxacin (the biologically active component) and 50% of its "mirror image" or enantiomer dextrofloxacine. Ofloxacin is used to treat certain infections including bronchitis, pneumonia, and infections of the skin, bladder, urinary tract, reproductive organs, and prostate gland. It works by killing bacteria that cause infections.

8. The product under consideration is classified under Chapter 30 of the Customs Tariff Act. The PUC has a specific HS code 3004 20 34 under Chapter 30 of Customs Tariff Act, 1975. However, subject goods being bulk drugs are also imported under HS codes 2915, 2916, 2918, 2941 etc. The customs classification is indicative only and in no way it is binding upon the product scope.

Like Article

9. The applicant has claimed that there is no known difference between the subject goods exported from subject country and that produced by the applicant. As submitted by the applicant, Ofloxacin produced by the domestic industry and imported from subject country are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions &

uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and are using the two interchangeably. The applicant has further claimed that two are technically and commercially substitutable and, hence, should be treated as 'like article' under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the Authority treats the subject goods produced by the applicant in India as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject country.

Countries involved

10. The present investigation is in respect of alleged dumping of the product under consideration from China (referred to as the "subject country").

Normal Value

11. Applicant has claimed that China should be treated as a non-market economy and normal value in case of China should be determined in accordance with para-7 and 8 of Annexure I of the Rules. The applicant has claimed normal value for China PR on the basis of cost of production in India, duly adjusted. In terms of Para 8 in Annexure 1 to the Rules it is presumed that the producers of the subject goods in China PR are operating under non market economy conditions.

12. In view of the above non-market economy presumption and subject to rebuttal of the same by the responding exporters from China PR, normal value of the subject goods in China PR has been estimated in terms of Para 7 of Annexure 1 to the Rules.

Export Price

13. The applicant has determined export price on the basis of data procured from transaction wise IBIS import data. Price adjustments have been claimed on account of ocean freight, marine insurance, commission, port expenses, inland freight, bank charges, and adjustment for VAT to arrive at the net export price.

Dumping Margin

14. The normal value has been compared with the export price at ex-factory level. There is sufficient prima facie evidence that the normal value of the subject goods in the subject country are higher than the ex-factory export price, indicating, that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject country. The dumping margin is estimated to be above de minimis.

Injury and Causal Link

15. Information furnished by the applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicant has furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to production and consumption in India, price suppression, price underselling and consequent significant adverse impact in terms of profits, return on capital employed, and cash flow to the domestic industry. There is sufficient prima facie evidence of the 'injury' being suffered by the domestic industry caused by dumped imports from subject country to justify initiation of an antidumping investigation.

Period of Investigation (POI)

16. The proposed period of investigation (POI) is 1st July 2015 to 30th June 2016. However, the injury investigation period has been considered and proposed to cover the periods April 13-March 14, April 14-March 15, April 15-March 16 and the proposed period of investigation.

Submission of information

17. The known exporters in the subject country, the Government of the subject country through their embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

The Designated Authority,
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,
Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce
4th Floor, Jeevan Tara Building, 5 Parliament Street,
New Delhi -110001.

18. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

Time limit

19. Any information relating to the present investigation and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-dumping Rules.

20. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to continue or otherwise the Antidumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation.

Submission of Information on Non-Confidential basis

21. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

22. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and five (05) copies of the non confidential version must be submitted by all the interested parties.

23. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

24. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

25. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

26. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

27. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

28. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

A. K. BHALLA, Addl. Secy. & Designated Authority